IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

भारत में राज्य-स्तरीय चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण पिछले दो दशकों में विभिन्न भारतीय राज्यों में चुनावी रुझानों और परिणामों का विश्लेषण

Dheeraj Solanki
M.A. Political Science
Ma- Govind Guru Tribal University, Banswara

सार

यह शोध पत्र 2004 से 2024 के बीच भारत के प्रमुख राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण देता है। इस पत्र में मतदान प्रतिशत के रुझान, दल-आधारित परिणाम, सत्ता-विरोधी लहर, महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय राजनीति का विश्लेषण किया गया है, जो भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आँकड़ों, लोकनीति-CSDS सर्वेक्षण रिपोर्टों और शैक्षणिक शोध के आधार पर किया गया है। शोध के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर से भिन्न स्थानीय कारकों से भारतीय राज्यों में चुनावी व्यवहार संचालित होता है।

मुख्य शब्दावली: तुलनात्मक चुनाव विश्लेषण, राज्य विधानसभा चुनाव, मतदान रुझान, सत्ताविरोधी लहर, भारत निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय दल, महिला प्रतिनिधित्व'

1. प्रस्तावना

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हर वर्ष विधानसभा चुनाव करता है। 28 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों वाले इस देश में राज्य-स्तरीय चुनाव केवल सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं हैं; ये देश की राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का महत्वपूर्ण संकेत भी हैं। भारतीय चुनावी राजनीति ने पिछले 2004 से 2024 तक अभूतपूर्व बदलाव देखा है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभाव कम हुआ है और क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बढ़ा है। मतदाता व्यवहार में परिपक्वता प्राप्त की है। विकास, सुशासन और व्यक्तित्व-आधारित मतदान का महत्व जाति और धर्म के साथ बढ़ा है। 2004

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/568

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 14, May 2026 Impact Factor: 8.2

से अब तक, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई, 2024) ने 100 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। प्रो. योगेन्द्र यादव और डॉ. सुहास पलशीकर की पुस्तक (2003) में कहा गया है कि भारत में राज्य-विशिष्ट दलीय व्यवस्था का उदय 'तीसरे चुनावी क्षण' में हो रहा है। 2004–2024 के डेटा के संदर्भ में, इस शोध पत्र में इस परिकल्पना का विश्लेषण किया गया है।

2. शोध प्रक्रिया और डेटा स्रोत

इस अध्ययन में मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा भारत निर्वाचन आयोग (eci.gov.in) के आधिकारिक परिणामों, निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टों, निर्धारण आयोग की रिपोर्टों और राज्य-स्तरीय निर्वाचन आयोग (ERO) रिपोर्टों से प्राप्त किया गया है। CSDS (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़) के नेशनल इलेक्शन स्टडीज़; इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) के शोध लेख, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट ADR (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) का विश्लेषण और विद्वानों की पुस्तकें द्वितीयक स्रोत हैं। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए, विभिन्न राज्यों की चुनावी श्रृंखलाओं का विश्लेषण किया गया है।

3. मतदान प्रतिशत (2004 से 2024 तक)

भारत में राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनावों से अधिक रहता है, क्योंकि मतदाता स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों से अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं। ECI की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, 2004 से 2023 के बीच राज्य विधानसभा चुनावों में औसत मतदान प्रतिशत 66.2% रहा, जो 2004 में 58.1% से महत्वपूर्ण वृद्धि है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, मणिपुर, नगालैंड और मिजोरम में मतदान प्रतिशत 80% से अधिक रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में मतदान ऐतिहासिक रूप से लगभग 60% रहा है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

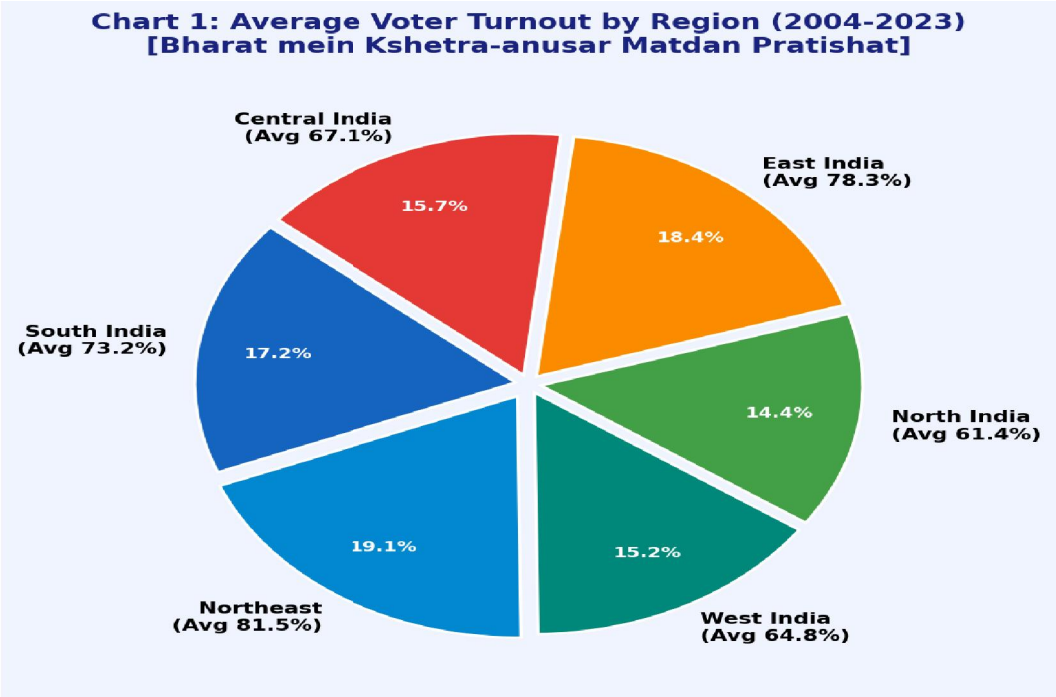

चार्ट 1: **क्षेत्र-अनुसार औसत मतदान प्रतिशत** (2004-2023) **स्रोत**: **भारत निर्वाचन आयोग**, 2023

क्षेत्रीय अंतर:-

भारतीय लोकतंत्र में मतदान प्रतिशत में क्षेत्रीय विभिन्नताएँ हैं। चार्ट 1 **में दिखाया गया है कि उत्तर भारत में केवल** 61.4% **की औसत मतदान दर है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में** 81.5% **है। दक्षिण भारत में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत स्थिर और उच्च रहा है, जो वहाँ की मजबूत दलीय संरचना और राजनीतिक बहस को दर्शाता है।** CSDS **के राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन** (2019) **के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में मतदान प्रतिशत** 8–12% **कम है। भारतीय लोकतंत्र को चिंता का विषय है 'शहरी उदासीनता'।** ECI **ने इसे दूर करने के लिए** SVEEP (**सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन**) **अभियान शुरू किया है।**

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

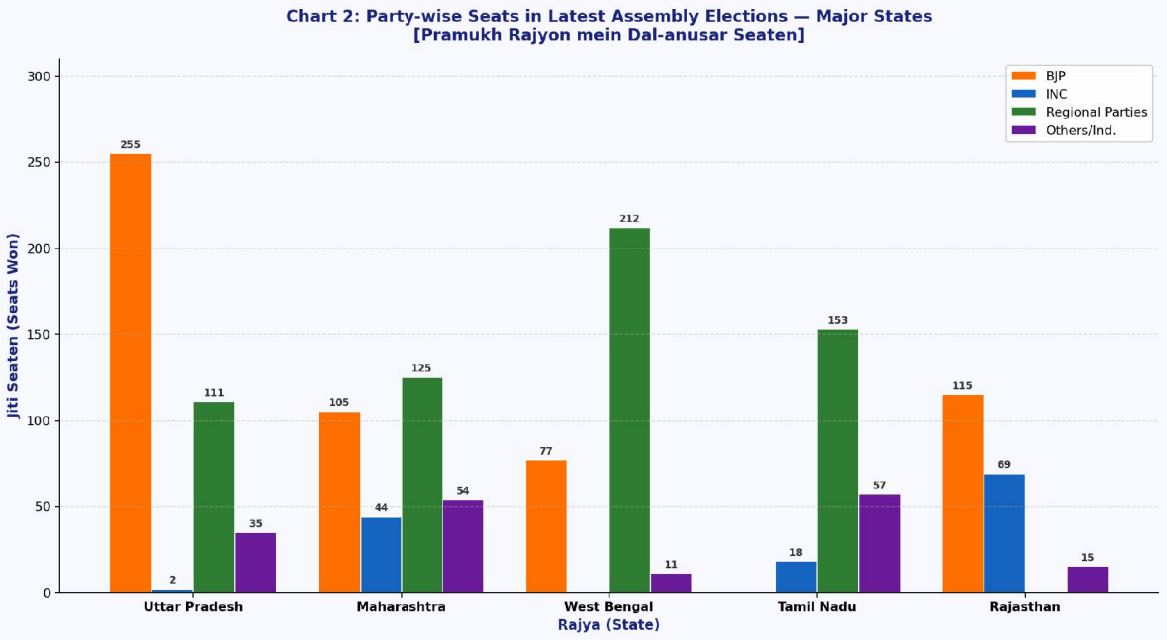

चार्ट 2: प्रमुख राज्यों में दल-अनुसार सीटें (नवीनतम चुनाव) स्रोत: ईसीआई, 2022–24

4. चुनावी परिणामों का विश्लेषण प्रमुख राज्यों

प्रमुख राज्यों के पिछले दो दशक के चुनावी सारांश निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

राज्य	चुनाव वर्ष	कुल सीटें	विजेता दल	मतदान % (लगभग)
उत्तर प्रदेश	2017, 2022	403	BJP (2017, 2022)	61.0 / 60.5
राजस्थान	2018, 2023	200	INC (2018), BJP (2023)	74.5 / 74.1
पश्चिम बंगाल	2016, 2021	294	TMC (2016, 2021)	84.5 / 76.9
महाराष्ट्र	2019, 2024	288	BJP+Shiv (2019)	60.4 / 61.6
तमिलनाडु	2016, 2021	234	AIADMK (2016), DMK (2021)	74.9 / 72.8
मध्य प्रदेश	2018, 2023	230	BJP (2018, 2023)	75.2 / 76.5

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 14, May 2026 Impact Factor: 8.2

राज्य	चुनाव वर्ष	कुल सीटें	विजेता दल	मतदान % (लगभग)
कर्नाटक	2018, 2023	224	BJP (2018), INC (2023)	72.4 / 73.2
दिल्ली	2015, 2020	70	AAP (2015, 2020)	67.1 / 62.6

तालिका 1: **प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों का सारांश** (2015-2024) **स्रोत**: **ईसीआई, 2024; एडीआर, 2024**

उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं क्योंकि यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2017 **में, भाजपा ने** 403 **सदस्यीय विधानसभा में ऐतिहासिक** 312 **सीटें जीतकर सरकार बनाई, जो** 1977 **के बाद का सबसे बड़ा बहुमत था।** 2022 **में,** BJP **ने** 255 **सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाई** (ECI, 2022)**। हिन्दुत्व की राजनीति, लोककल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ और योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में** 'INDIA' **गठबंधन की चुनौती के बावजूद** BJP **की सफलता का मुख्य कारण रहे।** SP **का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा, लेकिन वह सत्ता में वापस नहीं आ सकी।**

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) **की सफलता क्षेत्रीय दलों की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ममता बनर्जी ने** 2011 **में** 34 **वर्षीय वामपंथी शासन को समाप्त कर सत्ता में वापसी की.** 2021 **में, बीजेपी की तीव्र चुनौती के बावजूद, उन्होंने** 213 **सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। यहाँ मतदान प्रतिशत निरंतर** 75 **से** 85 **प्रतिशत के बीच रहता है, जो भारत में सबसे अधिक है (ईसीआई** (ECI), 2021) **द्वारा**

तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा आम है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके (AIADMK) और डीएमके (DMK) हर पाँच-पाँच वर्ष में सत्ता बदलते हैं। डीएमके (DMK) ने 2021 **में** 133 **सीटें जीतकर वापस आ गया। आईएनसी (INC) ने** 2023 **में कर्नाटक में** 135 **सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया, जो कांग्रेस की पिछली बड़ी जीत में से एक है।**

5. सत्ता-विरोधी लहर का विश्लेषण

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/568

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

भारतीय राज्य-स्तरीय चुनावों की एक प्रमुख विशेषता सत्ता-विरोधी लहर है। सीएसडीएस-लोकनीति के शोध (कुमार, 2019) के अनुसार, 1985-2019 के बीच भारत के राज्यों में सत्तारूढ़ दल को लगभग 57% मामलों में सत्ता गँवानी पड़ी है। तालिका 2 में हालिया चुनावों में इस प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है:

राज्य	पिछली सरकार	परिणाम	स्विंग (%)
राजस्थान (2018)	BJP — वसुंधरा राजे	INC को बहुमत (99 सीट)	-16.5%
छत्तीसगढ़ (2018)	BJP — रमन सिंह (15 वर्ष)	INC को भारी बहुमत	-11.2%
म.प्र. (2018)	BJP — शिवराज (13 वर्ष)	त्रिशंकु → INC सरकार	-8.4%
उ.प्र. (2022)	BJP — योगी आदित्यनाथ	BJP बहुमत (255 सीट)	+3.2%
प. बंगाल (2021)	TMC — ममता बनर्जी	TMC भारी बहुमत (213)	+5.8%
कर्नाटक (2023)	BJP — बोम्मई सरकार	INC को बहुमत (135)	-10.1%

तालिका 2: राज्यों में सत्ता-विरोधी लहर का विश्लेषण,स्रोत: ईसीआई, सीएसडीएस, एडीआर

किंतु यह प्रवृत्ति हर जगह नहीं है। 2022 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता-विरोधी लहर को पलटकर सफलता प्राप्त की, जबकि 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर से बहुमत हासिल किया। सत्ता-विरोधी लहर के सिद्धांत का अपवाद करते हुए नवीन पटनायक ने ओडिशा में 2000 से 2024 तक 24 वर्षों तक निरंतर मुख्यमंत्री का पद संभाला। शासन की विफलता, भ्रष्टाचार के आरोप, आर्थिक बदहाली, बेरोज़गारी और नेतृत्व की कमजोरी सत्ता-विरोधी लहर के प्रमुख कारण हैं। एडीआर (ADR) (2022) के अनुसार, अधिक बेरोज़गारी और महँगाई वाले राज्यों में सत्ता-विरोधी लहर थी।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/568

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

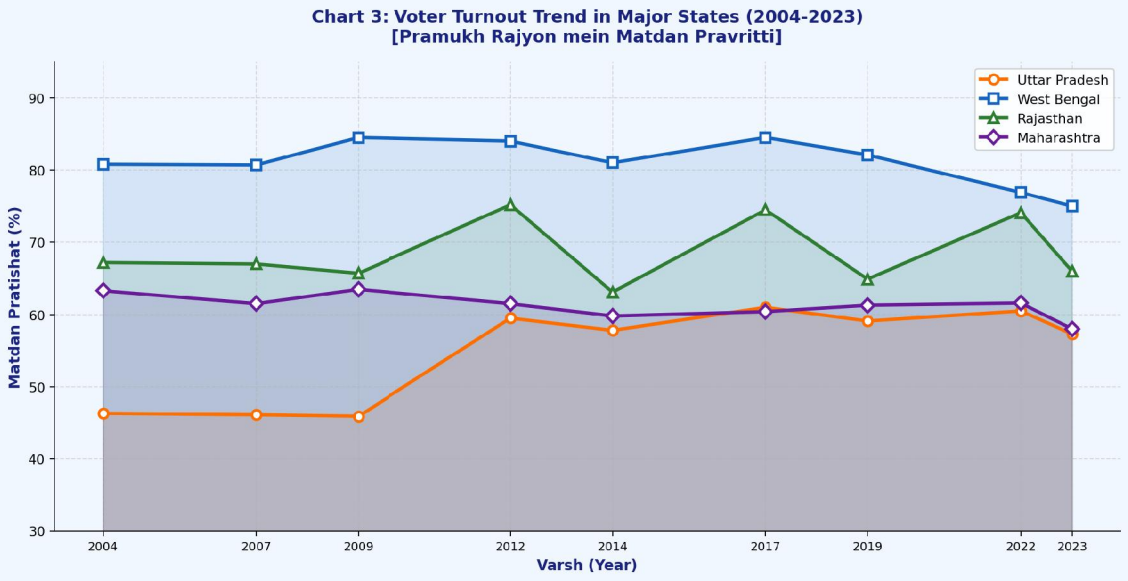

चार्ट 3: प्रमुख राज्यों में मतदान प्रतिशत की प्रवृत्ति (2004-2023) स्रोत: ईसीआई स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स

6. क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति

क्षेत्रीय दलों का विस्तार पिछले दो दशक में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी प्रवृत्ति रही है। राष्ट्रीय दलों (बीजेपी + आईएनसी) को 2004 में लगभग 52% राज्य विधानसभा सीटें मिली थीं, लेकिन 2022-23 के आंकड़े बताते हैं कि यह घटकर लगभग 42% रह गया है (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, 2023)। क्षेत्रीय दल, जैसे टीएमसी (पश्चिम बंगाल), वाईएसआरसीपी (YSRCP) (आंध्र प्रदेश), टीआरएस / बीआरएस TRS/BRS (तेलंगाना), बीजेडी (ओडिशा), आप (AAP) (दिल्ली, पंजाब), एसपी (SP) समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश), डीएमके–एआईएडीएमके (तमिलनाडु) और आप (AAP) (दिल्ली, पंजाब) ने अपने-अपने राज्यों में इतनी गहरी पकड़ बनाई है कि राष्ट्रीय दलों को उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। प्रो.ई. श्रीधरन (2014) ने इसे 'दोवीं अग्रणी पार्टी व्यवस्था' का उदय बताया है। क्षेत्रीय दल सफल रहे हैं, इसके कई कारण हैं: क्षेत्रीय नेतृत्व की पहचान, स्थानीय अस्मिता की राजनीति, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 14, May 2026 Impact Factor: 8.2

देना और केंद्र के खिलाफ 'विशेष दर्जा' की माँगों को भुनाना दूसरी ओर, राष्ट्रीय दल की कमजोरी स्थानीय नेतृत्व की कमी, गुटबाजी और स्थानीय संगठनों की कमी में है।

7. महिलाओं का प्रतिनिधित्व बदलाव

पिछले कुछ दशक में भारतीय विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी विश्व के कई लोकतंत्रों से कम है। विभिन्न राज्यों में इस प्रवृत्ति को तालिका 3 में दिखाया गया है:

राज्य	2004 (महिला %)	2012 (महिला %)	2018 (महिला %)	2022/23 (महिला %)
उत्तर प्रदेश	4.1%	7.9%	9.9%	11.6%
राजस्थान	6.5%	10.0%	12.0%	14.8%
पश्चिम बंगाल	10.1%	12.5%	13.3%	13.9%
तमिलनाडु	3.6%	6.1%	7.3%	8.2%
मध्य प्रदेश	6.0%	9.5%	10.0%	12.3%
दिल्ली	5.7%	10.0%	11.4%	12.9%

तालिका 3: प्रमुख राज्यों में महिला विधायक प्रतिशत (2004-2023) | स्रोत: ECI, PRS Legislative Research

राजस्थान में 2023 में 14.8 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 2022 में 11.6 प्रतिशत महिला विधायक चुने गए। 2023 में पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम", जो विधानसभाओं और लोकसभाओं में 33% आरक्षण देता है, इन आंकड़े बदल सकता है। एडीआर (ADR) की रिपोर्ट (2022) बताती है कि दलितों और पिछड़ी जातियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में 33 से 50% आरक्षण ने महिला नेतृत्व को मजबूत किया है, लेकिन इसका प्रभाव विधानसभाओं पर अभी भी सीमित है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 14, May 2026 Impact Factor: 8.2

8. तकनीकी बदलाव और चुनाव प्रक्रिया

2004 तक, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विद्युत मतदान मशीनों (ईवीएम) को पूरी तरह से लागू कर दिया था। इससे मतगणना की गति बढ़ी, खर्च कम हुआ और चुनावी धाँधली में काफी कमी आई। 2017 में मतदाता के विश्वास को बढ़ाने के लिए वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरुआत हुई।(ईसीआई,2017)

2018 के गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनावों से पहले, सी-विजिल और डिजिटल निगरानी ने सी-विजिल ऐप को लागू किया, जिससे मतदाता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट सीधे ईसीआई को भेज सकते हैं। चुनावी परिदृश्य को सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार ने पूरी तरह बदल दिया है। नकली खबरें और डेटा गोपनीयता दो नए मुद्दे बन गए हैं।

9. लोकतंत्र और चुनाव सुधार

भारतीय चुनाव प्रणाली में पिछले दो दशक में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। "एक राष्ट्र एक चुनाव" का विचार अभी भी चर्चा में है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की माँग पर दागी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाया था। 2003 में चुनावी बॉण्ड प्रणाली विवाद में थी और सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में इसे असंवैधानिक घोषित किया। लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की ओर से भी सकारात्मक संकेत मिलते हैं— मतदाता पंजीकरण में वृद्धि, युवा मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि, दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान और प्रवासी मतदाताओं के लिए पोस्ट बॉलोट का विस्तार अशोका यूनिवर्सिटी (2021) ने एक अध्ययन में पाया कि 75% से अधिक भारतीय मतदाताओं की लोकतंत्र में आस्था बनी हुई है, जो एशिया में सर्वाधिक है।

10. निष्कर्ष

इस तुलनात्मक अध्ययन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं: पहले, भारत में राज्य-स्तरीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे निर्णायक होते हैं और वे राष्ट्रीय चुनावों से स्वतंत्र रूप से होते हैं। द्वितीय, मतदान प्रतिशत में वृद्धि (2004 में 58% से 2023 में 68%+) भारत में लोकतंत्र की अधिक जागरूकता का संकेत है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 14, May 2026 Impact Factor: 8.2

तृतीय, क्षेत्रीय दलों का सुदृढ़ीकरण भारतीय संघवाद की शक्ति को बताता है। चतुर्थ, सत्ता-विरोधी लहर एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, लेकिन प्रभावी सरकार इसे रोक सकती है। पंचम, महिला प्रतिनिधित्व अभी भी कम है और इसे बढ़ाने के लिए संस्थागत प्रयास करने की जरूरत है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को और व्यापक बनाया जाए, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के लिए। ताकि धनबल की राजनीति को नियंत्रित किया जा सके, चुनावी खर्च की सीमा को वास्तविक बनाया जाए। "एक राष्ट्र एक चुनाव" के विचार पर सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की जाए। प्रो. ई. श्रीधरन और डॉ. मिलन वैष्णव के अध्ययन के अनुसार, भारतीय लोकतंत्र 'नाजुक' नहीं बल्कि 'जीवंत और विकासशील' है। दो दशक से अधिक समय के चुनावी आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय मतदाता परिपक्व हो रहा है और जाति-धर्म से परे शासन और विकास को अपना मतदान का आधार बना रहा है।

संदर्भ सूची

1. एडीआर (2022). एनालिसिस ऑफ असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, नई दिल्ली
2. अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (2021). डेमोक्रेसी इन इंडिया, परसेप्शन सर्वे, नई दिल्ली
3. सीएसडीएस–लोकनीति (2019). नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, नई दिल्ली
4. ईसीआई (2023). स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
5. ईसीआई (2024). वोटर टर्नआउट डेटा — स्टेट असेंबली इलेक्शंस 2004–2024, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
6. कुमार, एस. (2019). पोस्ट-पोल सर्वे: स्टेट असेंबली इलेक्शंस,लोकनीति–सीएसडीएस, ईपीडब्ल्यू, वॉल्यूम 54

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 14, May 2026
Impact Factor: 8.2

7. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (2023). स्टेट लेजिस्लेचर डेटा एंड एनालिसिस, नई दिल्ली
8. श्रीधरन, ई. (2014). पार्टी सिस्टम चेंज इन इंडियाज़ स्टेट्स, जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी, 25(4)
9. वैष्णव, एम. (2017). व्हेन क्राइम पेज़, मनी एंड मसल इन इंडियन पॉलिटिक्स, येल यूनिवर्सिटी प्रेस
10. यादव, वाई. एवं पल्शीकर, एस. (2003). पार्टी सिस्टम चेंज इन इंडियन स्टेट्स, वर्किंग पेपर, सीएसडीएस, नई दिल्ली
11. यूएनडीपी (2022). ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन साउथ एशिया
12. ज़ीगफेल्ड, ए. (2016). व्हाई रीजनल पार्टीज़? क्लाइंटेलिज़्म, एलीट्स, एंड द इंडियन पार्टी सिस्टम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस